

## उग्रवाद मुक्त समृद्ध उत्तर पूर्व

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। देश की सुरक्षा के लिए उत्तर-पूर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य है कि उत्तरपूर्व के सभी विवादों को 2022 तक समाप्त कर, 2023 में पूर्वोत्तर में शांति और विकास का नया युग शुरू करना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर की गरिमा, संस्कृति, भाषा, साहित्य और संगीत को समृद्ध करते हुए शांति प्रस्थापित करने के प्रयास किया है। हमारा मानना है कि शांति के बगैर विकास नहीं हो सकता, अगर रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर व्यक्ति को घर और बिजली चाहिए तो ये हथियार उठाकर नहीं हो सकता।

**उत्तरपूर्व क्षेत्र के लिए मा गृह मंत्री जी ने तीन उद्देश्यों को चिन्हीत किया है :**

1. पहला उद्देश्य, यहां की बोलियां, भाषाएं, नृत्य, संगीत, खान-पान, संस्कृति को संभालकर-संजोकर रखना और पूरे भारत में इसके लिए आकर्षण पैदा करना।
2. दूसरा, उत्तरपूर्व के सारे विवादों को समाप्त करके इसे शांतिपूर्ण क्षेत्र बनाना है।
3. और तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि उत्तरपूर्व को एक विकसित क्षेत्र बनाकर इसके आज़ादी-पूर्व के जीडीपी में योगदान के स्तर पर वापस लाने का प्रयास करना।

एक समय था, जब पूर्वोत्तर में आये दिन आन्दोलन, विवाद चलते थे। पिछले कुछ वर्षों में हमने सफलता से यह नेरेटिव सेट किया है कि विकास के लिए आंदोलन या विवाद की नहीं सहयोग और परिश्रम की जरूरत है।

पूर्व की सरकारों द्वारा किए गए कई समझौते बंद बक्सों में पड़े थे जिन पर धूल जम चुकी थी। लेकिन मा गृहमंत्री जी यह प्रयास किया कि लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं का स्थाई समाधान कर विकास के नए मापदंड स्थापित किये जाये, जैसे NLFT समझौता (त्रिपुरा), ब्रू शरणार्थी पुनर्वसन समझौता एवं बोडो शांति समझौता।

## कारबी आंगलोग : एक ऐतिहासिक समझौता

मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है कि जो हथियार डालेगा उसके लिए हमारा मन खुला है, लेकिन आतंक का साथ देने वालों के प्रति केंद्र तथा **राज्य सरकारों का दृष्टिकोण जीरो टॉलरेंस का होना चाहिए।** इसी कड़ी में मा गृह मंत्री जी की उपस्थिति में **कारबी-आंगलोग क्षेत्र में शांति प्रस्थापित** करने हेतु एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार तथा असम सरकार **कार्बी लोगों की न्यायोचित आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास** कर रही है। 1995 और 2011 में दो बार त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन पुरानी सरकारों द्वारा उदासीनता के चलते इन **समझौतों के बावजूद कारबी-आंगलोग में शांति प्रस्थापित नहीं हो सकी।**

मोदी सरकार ने **असम की क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखते हुए, कार्बी समूह की मांगों का एक व्यापक और अंतिम समाधान खोजने के प्रयास** में, कार्बी और कुकी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बातचीत की। प्रस्तावित ऐतिहासिक समझौता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में **मा गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा किये गए व्यापक प्रयासों का ही परिणाम है।**

## कारबी-आंगलोग शांति समझौते के प्रमुख बिंदु

- इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत, **फरवरी 2021** में ही **5 उग्रवादी संगठनों** ने हथियार डालें और उनके **1000 से अधिक सशस्त्र कैडर हिंसा को छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।**
- **कार्बी क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाओं को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार और असम सरकार द्वारा पांच वर्षों में 1000 करोड़ रुपये का विशेष विकास पैकेज दिया जाएगा।**

- यह समझौता असम की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को स्वायत्तता का अधिक से अधिक अधिकारों का हस्तांतरण करेगा
- यह समझौता कार्बी लोगों की संस्कृति, पहचान, भाषा, आदि की सुरक्षा और क्षेत्र के सर्वांगीन विकास को सुनिश्चित करेगा।
- इस समझौते में कार्बी सशस्त्र समूह हिंसा को त्यागने और देश के कानून द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं। जिसको ध्यान में रखते हुए इस समझौते में सशस्त्र समूहों के कैडरों के पुनर्वास का भी प्रावधान किया गया है।
- असम सरकार कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद क्षेत्र से बाहर रहने वाले कार्बी लोगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक कार्बी कल्याण परिषद की स्थापना की जाएगी।
- कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of the State) का संशोधन किया जाएगा।
- कुल मिलाकर, वर्तमान समझौते में कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को अधिक विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां देने का प्रस्ताव है।

### कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में अब तक की उपलब्धियां

- 23 फरवरी, 2021 को, कार्बी आंगलोंग के 5 (पांच) उग्रवादी संगठनों ने औपचारिक रूप से हथियार डाले।
- कार्बी आंगलोंग के 5 (पांच) उग्रवादी संगठनों के एक हजार से अधिक काडरों ने अपने हथियार और गोला-बारूद समर्पित कर दिये। एके-सीरीज़ राइफ़ल्स, एम16 राइफ़ल्स, एलएमजी, रॉकेट लॉन्चर आदि सहित कुल 338 हथियार और 11000 राउंड गोला-बारूद समर्पित कर दिये।

1. पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी (पीडीसीके),
  2. कार्बी लोंगरी नॉर्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ) ,
  3. कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स (केपीएलटी),
  4. कुकी लिबरेशन फ्रंट (केएलएफ़) और
  5. यूनाइटेड पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (यूपीएलए)
- पिछले समझौते के तहत घोषित कार्बी आंगलॉग ऑटोनोमस कौंसिल पैकेज के **350 करोड़ की लागत के 32 प्रकल्प आज पूर्णतः के विभिन्न चरणों में है**
  - मा गृह मंत्री जी द्वारा 19 अगस्त 2019 को दिल्ली में कार्बी भवन तथा दिमासा भवन की नींव रखी गई, जिसकी बहुत लम्बे समय से मांग थी
  - उत्तर-पूर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजना के तहत **22 करोड़ के प्रकल्प को मंजूरी दे दी गई है**
  - सेंट्रल पूल की एनएलसीपीआर स्कीम के तहत **200 करोड़ लागत के 20 प्रकल्प निर्माणाधीन है**
  - दीफू में असम पहाड़ी मेडिकल कालेज और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है और अकादमिक सत्र शुरू हो गया है।
  - बागोरी प्रवेश स्थान पर पर्यटक लॉज के विकास का काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।
  - दीफू में कैंसर देखभाल केंद्र के निर्माण का कार्य चल रहा है।

## पूर्वोत्तर के प्रमुख समझौते

माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मा गृह मंत्री जी ने पूर्वोत्तर के सभी विवादों के समाधान निश्चित समय सीमा में करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए श्री अमित शाह जी ने निरंतर बैठकें तथा सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ संवाद किये ।

❖ **NLFT त्रिपुरा समझौता : 10 अगस्त 2019** को मा गृह मंत्री जी की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। उसके तुरंत बाद दिनांक 13.08.2019 को आयोजित **आत्मसमर्पण समारोह में 88 काडरों ने 44 हथियारों** के साथ आत्मसमर्पण किया। समझौता ज्ञापन के अनुसार, त्रिपुरा के आदिवासियों के समग्र विकास के लिए त्रिपुरा सरकार को पांच वर्ष की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा **100 करोड़ रु. का एक विशेष आर्थिक विकास पैकेज (एसईडीपी)** प्रदान किया जाना है। इस 100 करोड़ रु. की राशि में से **40 करोड़ रु. की राशि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, पहले ही त्रिपुरा को जारी की जा चुकी है** तथा समझौते के अनुसार, शेष 60 करोड़ रु. की राशि त्रिपुरा को अगले तीन वर्ष की अवधि (2021-22 से 2023-24) के दौरान प्रदान कर दी जाएगी।

❖ **ब्रू समझौता : लगभग 661 करोड़ रु. की वित्तीय पैकेज के साथ त्रिपुरा में 6959 ब्रू परिवारों (37,136 व्यक्ति) को स्थायी रूप से बसाने** के लिए भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार तथा मिजोरम सरकार द्वारा ब्रू प्रवासियों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 16.01.2020 को मा गृह मंत्री जी के उपस्थिति में इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार, पुनः बसाए गए प्रत्येक ब्रू परिवार को **फिक्स्ड डिपोजिट के रूप में चार लाख रु. की वित्तीय सहायता, मुफ्त राशन, दो वर्षों के लिए पांच हजार रु. प्रति माह की राशि, 1.5 लाख रु. की दर से आवास सहायता तथा 30x40 वर्गफुट का एक भूमि प्लॉट** दिया जाएगा। ब्रू प्रवासियों के पुनर्वास के लिए त्रिपुरा सरकार को वित्त वर्ष **2019-20 के दौरान, 128.38 करोड़ रु. तथा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, 140 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई थी।**

त्रिपुरा सरकार ने प्रारंभ में ब्रू प्रवासियों को बसाने के लिए छह जिलों में 14 लोकेशन निर्धारित कीं तथा ऐसे सभी 13 प्रस्तावों, जिनमें वन अनापत्ति अपेक्षित थी, को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

अब तक, चार स्थानों पर 2110 परिवारों को प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं जिनमें से 1426 ब्रू परिवारों को आवास निर्माण संबंधी सहायता प्रदान कर दी गई है।

- ❖ **बोडो शांति समझौता** : मा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में दीर्घ काल से लंबित **बोडो मुद्दे का समाधान** करने के लिए भारत सरकार, असम सरकार तथा बोडो समूहों के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 27.01.2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के उपरांत एनडीएफबी समूहों के 1615 काडरों ने दिनांक 30.01.2020 को अपने हथियार आत्मसमर्पित किए। एनडीएफबी समूहों का दिनांक 09-10 मार्च, 2020 को विघटन हो गया। समझौता-ज्ञापन के अनुसार, असम में बोडो क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए **तीन वर्ष की अवधि के दौरान 1500 करोड़ रु.** (750 करोड़ रु. डोनर मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तथा 750 करोड़ रु. असम सरकार द्वारा) **का एक विशेष विकास पैकेज** (एसडीपी) प्रदान किया जाएगा।

### **सुरक्षित पूर्वोत्तर**

- वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वर्ष **2019 और 2020 में पिछले दो दशकों के दौरान सबसे कम विद्रोह** की घटनाएं तथा नागरिकों और सुरक्षा बलों की हताहत की घटनाएं
- जहाँ **2014 में पूर्वोत्तर में 824 हिंसा की घटनाएँ हुई थी** जिसमें 212 निर्दोष नागरिक मारे गए थे, वह आज घट होकर **2020 में केवल 162 ऐसी घटनाएँ घटित हुयीं**, जिसमें केवल 2 नागरिक मारे गए

- वर्ष 2014 की तुलना में, वर्ष 2020 में विद्रोही घटनाओं में 80% की कमी हुई है। इसी प्रकार, इस अवधि में, मारे गए सुरक्षा बलों की संख्या 75% तथा सिविलियन की मृत्यु 99% कम हुई है।
- पिछले 2 वर्षों में 3922 उग्रवादियों ने 873 हथियारों के साथ सरेंडर किया है।
- 2014-15 से, विभिन्न सुरक्षा मदों व आत्मसमर्पण किए विद्रोहियों के पुनर्वास पर पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा किए गए सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) की प्रतिपूर्ति के लिए उनको 2002 करोड़ रु. की राशि जारी की है।

### सीमा क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर

- प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय करते हुए सीमा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए गृह मंत्रालय को "उपयुक्त सरकार" घोषित किया गया है
- भारत-चीन सीमा पर निम्न निर्माण कार्यों को मंजूरी:
  - आईसीबीआर -II तहत 683 किमी लंबी, 32 सड़क निर्माण; लागत 12,435 करोड़
  - अरुणाचल प्रदेश में सीमा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 18 फुट ट्रेक्स और अन्य संरचनाओं के निर्माण; लागत – 1162 करोड़
- त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश सीमा पर लगभग 23.85 किमी लंबी बाड़ लगाने का काम पूरा

### पूर्वोत्तर का चहुंमुखी विकास:

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध है। भारत सरकार एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत पूर्वोत्तर को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाला एक आर्थिक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास के लिए वर्ष 2014 से मार्च, 2021 तक कुल 2 लाख 65 हजार 513 करोड़ रूपये धनराशि खर्च की गई है।

- 14वे वित्त आयोग में 13वे वित्त आयोग की तुलना में केंद्रीय करों में 251% अधिक राशि मिली है। वहीं 14वे वित्त आयोग में 13वे वित्त आयोग की तुलना में कुल 183% अधिक राशि। डोनर मंत्रालय के बजट में भी 2014-15 की तुलना में 2019-20 में 65% वृद्धि की गई है..
- जनवरी 2020 के दौरान, मा गृह मंत्री जी के NEC में दिए गए निर्देश के अनुसार डोनर मंत्रालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया और **वंचित क्षेत्रों, समाज के वंचित/उपेक्षित वर्गों और उभरते प्राथमिकता** वाले क्षेत्रों के केंद्रित विकास के लिए मौजूदा 'एनईसी की योजनाओं' के तहत नई परियोजनाओं के लिए **एनईसी के आवंटन का 30% निर्धारित** किये गए है। पूर्वोत्तर राज्यों में इसके तहत 2020-21 के दौरान 214 करोड़ रुपये की 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई ।
- 13वें वित्त आयोग में NEC को 3449 करोड़ का बजट आवंटित, इसके विपरीत 14वें वित्त आयोग में 5348 करोड़ का बजट आवंटित/. यह लगभग डेढ़ गुना बढ़ोतरी है.



## टिपणी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने न केवल सायकोलोजिकल अंतराल को कम किया बल्कि विकास के एक मॉडल के रूप में पूर्वोत्तर को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। एक जमाना था, जब दिल्ली को यहाँ पराया समझा जाता था... लेकिन मोदी जी ने पिछले 7 वर्ष में भारत सरकार को पूर्वोत्तर में लाने का काम किया है।

पहले पूर्वोत्तर में घुसपैठ, आतंक और भ्रष्टाचार की बात होती थी लेकिन आज विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की चर्चा होती है। उत्तर-पूर्व की सभी जटिल समस्याओं का समाधान का हमारा लक्ष्य है। मोदी सरकार ने विज़न देखा है ड्रग फ्री और टेररिज्म फ्री और विकसित नॉर्थईस्ट का ! सभी प्रकार के विवाद को परस्पर विचार-विमर्श कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में शीघ्रतापूर्वक सुलझाने में मोदी सरकार जरूर कामियाब होगी।

सशस्त्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिंसा को त्यागने और देश के कानून द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। यह समझौता कार्बी ऐंगलॉग स्वायत्त परिषद को अधिक स्वायत्तता; कार्बी की पहचान, भाषा, संस्कृति आदि की सुरक्षा; सशस्त्र समूहों के संवर्गों का पुनर्वास; और असम की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए कार्बी आंगलॉग का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेगा। यह माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के 'उग्रवाद मुक्त समृद्ध उत्तर पूर्व' के विज़न को पूरा करने में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा।